

रेवतीरतन लाल के बेटे, और अन्य *बहुत* हरियाणा राज्य के माध्यम से
भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, फरीदाबाद (एन.सी. जैन, जे.)

एन. सी. जैन, जे.

रेवती पुत्र रतन लाल और अन्य-

अपीलकर्ता।

बनाम

भूमि अधिग्रहण कलेक्टर,

फरीदाबाद के माध्यम से हरियाणा राज्य -

प्रतिवादी।

नियमित प्रथम अपील सं. 1497 से 1982 तक।

11 जुलाई, 1989

*भूमि अधिग्रहण अधिनियम (1989 का अधिनियम 1) धारा 18 और 25 - संदर्भ
- मुआवजे का निर्धारण करने के लिए सिविल कोर्ट की शक्ति - सिविल कोर्ट द्वारा
तकनीकी दृष्टिकोण नहीं लिया जाना चाहिए - कानून के सिद्धांत में कहा गया है।*

*अभिनिर्णित किया जाता है कि कानून के निम्नलिखित सिद्धांतों को अच्छी
तरह से तैयार किया जा सकता है: -*

- (i) मुआवजे की एक विशेष राशि प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ मांगते समय कलेक्टर से कोई अनुरोध नहीं किया जा सकता है और यदि ऐसा अनुरोध किया जाता है, तो इसे अधिशेष के रूप में माना जाएगा।
- (ii) कलेक्टर केवल सिविल कोर्ट को मुआवजे के निर्धारण के लिए अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ दे सकता है। यहां तक कि अगर वह सहमत है, तो वह एक ज़मींदार द्वारा मांगी गई क्षतिपूर्ति नहीं दे सकता है।
- (iii) अधिनियम की धारा 18 के तहत केवल सिविल कोर्ट और सिविल कोर्ट को ही मुआवजे का निर्धारण करने का अधिकार है। भूमि अधिग्रहण की धारा 25 के असंशोधित प्रावधान के तहत भूस्वामी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस के जवाब में उन्होंने जो दावा किया था, उसे देने के लिए अधिनियम को बाध्य किया जा सकता था। अधिनियम की धारा 25 के संशोधित प्रावधानों के तहत, भूमि मालिक को अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस का जवाब देते समय किसी भी दावे के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

- (iv) *भाग सिंह* के मामले (सुप्रा) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों की गंभीरता के संबंध में भूमि अधिग्रहण मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा कोई तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए।
- (v) जहां कहीं भी दो विचार संभव हों, जहां तक संभव हो, तकनीकी दृष्टिकोण लेने से बचना चाहिए, जब तक कि ऐसा दृष्टिकोण कानून के स्पष्ट प्रावधान के साथ सीधे टकराव में न हो। यह सिद्धांत भूमि अधिग्रहण के मामलों में अधिक बल के साथ लागू होता है जहां भूमि का अधिग्रहण भूस्वामी की इच्छा के खिलाफ किया जाता है। (पैरा 5)

फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री सुरिंदर सरूप के न्यायालय के दिनांक 24 अगस्त, 1982 के आदेश से प्रथम अपील दायर की गई जिसमें याचिकाकर्ताओं को 10,000/- रुपये प्रति माह की दर से मुआवजे का अधिकार दिया गया था। (ख) विवादित भूमि के लिए 6 प्रतिशत प्रति वर्ग गज की दर से ब्याज देना होगा और यह भी आदेश देना होगा कि इसके अतिरिक्त, उनके पास बढ़े हुए मुआवजे पर 15 प्रतिशत अनिवार्य अधिग्रहण शुल्क के साथ-साथ कब्जा लेने की तारीख से भुगतान की तारीख तक संदर्भ की लागत के साथ प्रति वर्ष 6 प्रतिशत ब्याज भी होगा।

दावा:- भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भित। अपील में दावा:- मुआवजे में वृद्धि के लिए।

अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम. एल. सरिन, अधिवक्ता आशीष हांडा।
एस. सी. मोहंता, ए.जी., एन.के. कपूर, एडवोकेट, के साथ, प्रतिवादी-एस टेट के लिए।

रेवतीरतन लाल के बेटे, और अन्य *बहुत* हरियाणा राज्य के माध्यम से भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, फरीदाबाद (एन.सी. जैन, जे.)

आदेश

नरेश चंद्र जैन, जे(मौखिक)

(1) मेरा यह निर्णय 1982 की दो अपीलों अर्थात् आरएफए संख्या 1497 और 1498 का निपटारा करेगा, क्योंकि वे 24 अगस्त, 1982 के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के एक सामान्य फैसले से उत्पन्न होती हैं। चुनौती के तहत दिए गए पुरस्कारों के अनुसार, अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य 12.50 रुपये प्रति वर्ग गज निर्धारित किया गया है। हालांकि, अपीलकर्ता-दावेदारों को केवल 6 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा दिया गया है क्योंकि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के अनुसार उन्होंने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत अपने आवेदनों में इतना दावा किया था। दूसरे शब्दों में, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का विचार था कि यद्यपि अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य 12.50 रुपये प्रति वर्ग गज था, लेकिन पहले दिए गए दो पुरस्कारों ए.एल. और ए.2 में निर्धारित किया गया था, फिर भी अपीलकर्ताओं को उपरोक्त दर पर मुआवजा नहीं दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत अपने आवेदनों में 6 रुपये प्रति वर्ग गज से अधिक का दावा नहीं किया था।

(2) पक्षकारों के वकीलों को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के निष्कर्ष को न तो कानून में और न ही तथ्यों पर कायम रखा जा सकता है। अधिनियम की धारा 18 के तहत आवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि याचिकाकर्ता ने उसमें कहा था कि निर्णय दिया गया है जिसमें अपीलकर्ता उस भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे जिसे अधिग्रहित किया गया है और अपीलकर्ता-दावेदार निर्णय से असंतुष्ट थे जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया और कलेक्टर से अनुरोध किया कि संदर्भ आवेदन में उल्लिखित आधारों पर मूल्यांकन और मुआवजे के प्रश्न के निर्धारण के लिए मामले को अधिनियम की धारा 18 के तहत सिविल कोर्ट में संदर्भित करें। ग्राउंड नं 12 में। (क) यह कहा गया था कि अधिग्रहीत की गई भूमि का मूल्य बहुत कम आंका गया था और इसका बाजार मूल्य 6 रुपये प्रति वर्ग गज से कम नहीं होना

चाहिए था। संदर्भ आवेदन के अंत में, इस आशय का कोई अनुरोध नहीं किया गया था कि दावेदारों को 6 रुपये प्रति वर्ग गज प्रदान किया जाए। संदर्भ आवेदन में की गई बातों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई अनुरोध किया गया था कि दावेदारों को 6 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा दिया जाए। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश आवेदन में कुछ और पढ़ रहे थे जिसका उल्लेख उसमें नहीं किया गया है। यह मामले का एक पहलू है।

(3) इस मामले का दूसरा पहलू यह है कि अधिनियम की धारा 18 के उपबंधों का दायरा क्या है जिसमें कलेक्टर से किसी पीड़ित व्यक्ति के कहने पर संदर्भ मांगा जाता है जो अधिनिर्णय स्वीकार नहीं करता है। अधिनियम की धारा 18 में सिविल न्यायालय के संदर्भ के लिए एक आवेदन दायर करने की परिकल्पना की गई है जब भी कोई इच्छुक व्यक्ति निर्णय स्वीकार नहीं करता है। इच्छुक व्यक्ति द्वारा अधिनिर्णय स्वीकार न किए जाने की स्थिति में, कलेक्टर को लिखित आवेदन में यह अपेक्षित है कि मामले को कलेक्टर द्वारा न्यायालय के निर्धारण के लिए भेजा जाए, चाहे उसकी आपतियां भूमि की माप, मुआवजे की राशि, या मुआवजे के बंटवारे के बारे में हों। चूंकि सिविल न्यायालय के संदर्भ के लिए कलेक्टर को आवेदन किया जाता है, इसलिए कलेक्टर को मुआवजे की एक विशेष राशि प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि अगर ऐसी प्रार्थना की जाती है और भले ही कलेक्टर इच्छुक व्यक्ति के अनुरोध को मंजूरी देने के लिए सहमत हो, तो वह दावेदार को मुआवजे की राशि नहीं दे सकता है। अधिनिर्णय की घोषणा के बाद उसके पास इस मामले में अधिकार क्षेत्र नहीं रह जाता है। इसके बाद केवल सिविल कोर्ट और सिविल कोर्ट ही अधिनियम की धारा 18 के अर्थ और दायरे के भीतर विचार किए गए प्रश्नों को निर्धारित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि यदि कोई विशेष पीड़ित भूमि-स्वामी कलेक्टर से अधिनियम की धारा 18 के तहत आवेदन में कलेक्टर के पुरस्कार में दी गई राशि की तुलना में अधिक राशि तय करने का अनुरोध करता है, तो ऐसे अनुरोध को कानून की नजर में अधिशेष के रूप में माना जाना चाहिए।

(4) कुल मिलाकर, इस न्यायालय का विचार है कि मुआवजा प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ मांगते समय कलेक्टर से कोई अनुरोध नहीं

रेवतीरतन लाल के बेटे, और अन्य *बहुत* हरियाणा राज्य के माध्यम से भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, फरीदाबाद (एन.सी. जैन, जे.)

किया जाता है और यदि ऐसा अनुरोध किया जाता है, तो यह दावेदार को बाध्य नहीं करेगा। इस न्यायालय का यह भी विचार है कि कलेक्टर द्वारा संदर्भ दिए जाने के बाद उचित क्षतिपूर्ति के निर्धारण का निर्णय सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अधिनियम की धारा 9 के तहत दिए गए नोटिस का जवाब देने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा दावे दायर किए जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को उसके दावे के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया जा सकता था, तो ऐसा केवल तभी किया जा सकता था जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 25 के तहत नोटिस के जवाब में ऐसा दावा किया गया हो। असंशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 25 में किए गए एक विशिष्ट प्रावधान के कारण यह कानूनी स्थिति थी, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"धारा 25। मुआवजे की राशि के बारे में नियम- (1) जब आवेदक ने धारा 9 के तहत किसी नोटिस के अनुसरण में *मुआवजे का* दावा किया है, तो न्यायालय द्वारा उसे दी गई राशि इस तरह दावा की गई राशि से अधिक नहीं होगी या धारा 11 के तहत कलेक्टर द्वारा दी गई राशि से कम नहीं होगी।

(2) जब आवेदक ने ऐसा दावा करने से इनकार कर दिया है या ऐसा दावा करने के लिए पर्याप्त कारण (न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी जाने के लिए) के बिना छोड़ दिया है, तो न्यायालय द्वारा दी गई राशि किसी भी मामले में कलेक्टर द्वारा दी गई राशि से अधिक नहीं होगी।

यहां तक कि संसद ने भी ऐसे दावेदारों को बाध्य नहीं करना उचित समझा, जिन्होंने अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस के जवाब में मुआवजे की एक विशेष राशि की मांग की है, और यही कारण है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 25 को 1984 के अधिनियम 68 द्वारा संशोधित किया गया है। संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 25 इस प्रकार है:

"धारा 25। न्यायालय द्वारा मुआवजे की राशि कलेक्टर द्वारा दी गई राशि से कम नहीं होनी चाहिए।

अदालत द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि धारा 11 के तहत कलेक्टर द्वारा दी गई राशि से कम नहीं होगी।

रेवती, रतन लाई के बेटे, और अन्य **बहुत** हरियाणा राज्य के माध्यम से भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, इजारियाबा (एम. सी. जैन, जे.)

अधिनियम की धारा 25 का संशोधन, जैसा कि स्पष्ट है, न्यायसंगत दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसे अदालतों को व्यक्ति को सीमित राहत के लिए बाध्य नहीं करके लेना चाहिए, जिसका दावा उसके द्वारा किया जाता है। कानून में भूस्वामी को जो भी राहत मिलती है, उसे अनुमति दी जानी चाहिए, भले ही उसके द्वारा किए गए दावे पर ध्यान दिए बिना। यह विधायिका का इरादा है जो अधिनियम की धारा 25 के असंशोधित और संशोधित प्रावधानों के अवलोकन से प्रकट होता है। इसे ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा उठाए गए तकनीकी दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए कोई जगह नहीं बची है। एक बार जब इसी तरह की परिस्थिति वाले अन्य भूमि-मालिकों को 12.50 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजे के अनुदान का हकदार माना जाता है और अपीलकर्ताओं के मामले को पहले के फैसलों द्वारा कवर किया जाता है, तो अपीलकर्ताओं को मुआवजे की समान राशि से इनकार करना काफी अन्यायपूर्ण होगा, जिनकी भूमि उसी अधिसूचना के तहत अधिग्रहित की गई है। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ताओं को 6 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा देना; जब वे 12.50 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजे के हकदार हैं, तो यह मामले का तकनीकी दृष्टिकोण होगा। *भाग सिंह और अन्य बनाम अन्य* मामले में सर्वोच्च न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ (1) ने इस सवाल पर विचार करते हुए मामले पर तकनीकी दृष्टिकोण लेने से इनकार कर दिया कि क्या उन व्यक्तियों को अदालत-शुल्क में कमी को पूरा करने के लिए समय दिया जाना चाहिए जिन्होंने प्रारंभिक चरण में उचित अदालत-शुल्क नहीं दिया था। उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप द्वारा किए गए निम्नलिखित आक्षेपों को लाभ के साथ पढ़ा जा सकता है:-

"हमारा विचार है कि जब एकल न्यायाधीश और खंडपीठ ने यह विचार लिया कि जिन दावेदारों की भूमि पंजाब राज्य द्वारा अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत जारी अधिसूचना के तहत अधिग्रहित की गई थी, वे बढ़े हुए मुआवजे के हकदार थे और अपीलकर्ताओं का मामला समान स्तर पर था। अपीलकर्ताओं को घाटे की अदालत-शुल्क का भुगतान करने का अवसर दिया जाना चाहिए था ताकि, अन्य याचिकाकर्ताओं की तरह, उन्हें भी दूसरों

के समान दर पर बढ़ा हुआ मुआवजा मिल सके। विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ को हमारी राय में तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए था और अपीलकर्ताओं को बढ़े हुए मुआवजे के लाभ से केवल इसलिए वंचित नहीं करना चाहिए था क्योंकि उन्होंने शुरू में अदालत-शुल्क की उचित राशि का भुगतान नहीं किया था। यह याद रखना चाहिए कि यह दो निजी नागरिकों के बीच का विवाद नहीं था, जहां क्लेम को उसके द्वारा किए गए दावे तक सीमित रखना और उसे दावे से अधिक राशि नहीं देना काफी न्यायसंगत और वैध होगा, हालांकि ऐसे मामले में भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां दावे से अधिक राशि दावेदार को दी जा सकती है, उदाहरण के लिए जहां एक राशि का दावा किया जाता है। जैसा कि एक खाते के निचले हिस्से में देय है। उनका दावा अपीलकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ उनकी भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजे के लिए किया गया था और कानून के तहत, राज्य अपीलकर्ताओं को अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य था और यदि विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच के निर्णयों को स्वीकार करते हुए, अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य भूमि अधिग्रहण कलेक्टर या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए मूल्य से अधिक था, ऐसा कोई कारण नहीं है कि अपीलकर्ताओं को इस तरह से निर्धारित बाजार मूल्य के भुगतान के लाभ से वंचित किया जाना चाहिए था। अपीलकर्ताओं को इस लाभ से वंचित करना राज्य सरकार को वास्तविक बाजार मूल्य से कम के भुगतान पर अपीलकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण करने की अनुमति देने के समान होगा। ऐसे मामले हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, कृषि सुधार कानून के तहत, भूमि धारक को सामाजिक न्याय के मामले के रूप में, कुछ लोगों के हाथों में भूमि के केंद्रीकरण को समाप्त करने और इसके न्यायसंगत वितरण को लाने की दृष्टि से, उस भूमि से वंचित किया जा सकता है जिस पर उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से खेती नहीं की जा रही है या जो बहुत कम मुआवजे के भुगतान के साथ सीलिंग क्षेत्र से अधिक है। लेकिन जहां

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के तहत भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, वहां वास्तविक बाजार मूल्य का भुगतान किए बिना धारक को उसकी भूमि से वंचित करना उचित और न्यायसंगत नहीं होगा, जबकि कानून, कई शब्दों में, घोषणा करता है कि उसे इस तरह के बाजार मूल्य का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार को वह करना चाहिए जो नागरिकों के लिए उचित और न्यायपूर्ण हो और जहां तक संभव हो, उन मामलों को छोड़कर जहां कर या राजस्व प्राप्त किया जाता है या बिना किसी विरोध के वसूल किया जाता है या जहां राज्य सरकार अन्यथापूर्वाग्रह से ग्रस्त होगी, नागरिक के वैध और न्यायसंगत दावे को विफल करने के लिए तकनीकी याचिका नहीं उठानी चाहिए। इसलिए, हमारा विचार है कि, वर्तमान मामले में, डिवीजन बेंच के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश को अपीलकर्ताओं को घाटे की अदालत की फीस का भुगतान करने की अनुमति देनी चाहिए थी और उन्हें उच्च दर या उनके द्वारा निर्धारित दरों पर मुआवजा देना चाहिए था।

(5) ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, कानून के निम्नलिखित सिद्धांत को अच्छी तरह से तैयार किया जा सकता है:

- (i) मुआवजे की एक विशेष राशि प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ मांगते समय कलेक्टर से कोई अनुरोध नहीं किया जा सकता है और यदि ऐसा अनुरोध किया जाता है, तो इसे अधिशेष के रूप में माना जाएगा।
- (ii) कलेक्टर केवल सिविल कोर्ट को मुआवजे के निर्धारण के लिए अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ दे सकता है। यहां तक कि अगर वह सहमत है, तो वह एक भूस्वामी द्वारा मांगी गई क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं कर सकता है।
- (iii) अधिनियम की धारा 18 के तहत केवल सिविल कोर्ट और सिविल कोर्ट को ही मुआवजे का निर्धारण करने का अधिकार है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 25 के असंशोधित प्रावधानों के तहत भूस्वामी को - उतना दावा देने के लिए बाध्य किया जा सकता था जितना उसने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस के जवाब में किया था। अधिनियम की धारा 25 के संशोधित प्रावधानों के तहत, भूमि मालिक को अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस का जवाब देते समय किसी भी दावे के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
- (iv) *भाग सिंह के मामले* (सुप्रा) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों की तर्ज पर भूमि अधिग्रहण मामलों में सिविल कोर्ट द्वारा कोई तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए।
- (v) पीठ ने कहा, 'जहां भी दो विचार हो सकते हैं, तकनीकी दृष्टिकोण अपनाते हुए, जितना संभव हो सके, तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा दृष्टिकोण कानून के स्पष्ट प्रावधान के साथ सीधे मेल नहीं खाता है। यह सिद्धांत उन भूमि अधिग्रहण मामलों में अधिक लागू होता है जहां

भूमि का अधिग्रहण भूस्वामी की इच्छा के खिलाफ किया जाता है।

(6) ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में, अपीलकर्ताओं द्वारा दायर दोनों अपीलों को लागत के साथ अनुमति दी जाती है और वे 12.50 प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजे के अनुदान के हकदार हैं। उन्हें पूरी राशि पर अधिनियम की धारा 23 (1-ए), 23 (2) और 28 के संशोधित प्रावधानों के राज्य लाभ प्रदान करने का भी हकदार माना जाता है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पारस चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा।